

सतत निवेश के लिए भारत की अवधारणा: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भूमिका और प्रभाव POOJA BHAGAT

Guest Faculty, School of Open Learning, University of Delhi

सारांश:

यह समीक्षा पत्र स्थायी निवेश के लिए भारत की अवधारणा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी भूमिका और प्रभाव की जांच करता है। पेपर स्थायी निवेश के मूलभूत सिद्धांतों और आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में इसके महत्व की पड़ताल करता है। यह स्थायी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने, बाजार पहुंच का विस्तार करने, सहयोग और ज्ञान हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने, व्यापार समझौतों और नीतियों को आकार देने और वित्तीय प्रदर्शन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने में स्थायी निवेश की भूमिका का विश्लेषण करता है। समीक्षा में पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था, शासन और सतत विकास में इसके वैश्विक नेतृत्व सहित विभिन्न पहलुओं पर स्थायी निवेश के लिए भारत की अवधारणा के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त, पेपर भारत में स्थायी निवेश को आगे बढ़ाने के लिए वित्तपोषण, क्षमता निर्माण, डेटा उपलब्धता, नीतिगत ढांचे और सहयोग तक पहुंच के महत्व पर जोर देते हुए चुनौतियों और भविष्य की दिशाओं की पहचान करता है। निष्कर्ष प्रमुख निष्कर्षों का एक व्यापक सारांश प्रदान करता है और भविष्य में स्थायी निवेश को चलाने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने और उभरते क्षेत्रों की खोज करने की क्षमता पर प्रकाश डालता है।

मूल शब्द: भारत की अवधारणा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, सामाजिक विकास

परिचय

भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में, दीर्घकालिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास [1] को प्राप्त करने में स्थायी निवेश के महत्व को पहचानता है। स्थायी निवेश की अवधारणा वित्तीय संसाधनों के आवंटन को उन परियोजनाओं और पहलों के लिए संदर्भित करती है जो वित्तीय रिटर्न प्रदान करते समय सकारात्मक पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासन (ESG) परिणाम उत्पन्न करते हैं [2]। इस पत्र का उद्देश्य स्थायी निवेश के लिए भारत की अवधारणा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी भूमिका और प्रभाव का पता लगाना है। पर्यावरण और सामाजिक चुनौतियों के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण निवेश निर्णयों में स्थिरता के एकीकरण ने विश्व स्तर पर गति प्राप्त की है [3]। सतत निवेश सतत विकास के सिद्धांतों, संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने, सामाजिक समावेशिता और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं [4] के साथ जुड़ा हुआ है। स्थायी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच की कड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि में योगदान देता है और एक अधिक टिकाऊ वैश्विक अर्थव्यवस्था [5] के लिए संक्रमण की सुविधा प्रदान करता है।

सतत निवेश: अवधारणाएं और सिद्धांत

सतत निवेश एक दृष्टिकोण है जिसमें परियोजनाओं, व्यवसायों और परिसंपत्तियों के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन शामिल है, जिसका उद्देश्य सकारात्मक पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासन (ईएसजी) परिणाम उत्पन्न करना है, साथ ही वित्तीय रिटर्न देना भी है [6]। यह अवधारणा निवेश निर्णयों में स्थिरता के विचारों के एकीकरण और जिम्मेदार और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर देती है। संयुक्त राष्ट्र के उत्तरदायी निवेश के सिद्धांत (पीआरआई) स्थायी निवेश प्रथाओं के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। PRI निवेशकों को उनके निवेश विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में ESG कारकों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है [7]। ईएसजी मानदंडों पर विचार करके, निवेशक उन कंपनियों की पहचान और समर्थन कर सकते हैं जो स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं, सामाजिक जिम्मेदारी और सुशासन का प्रदर्शन करती हैं। एक और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त ढांचा ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) है। जीआरआई कंपनियों को उनके स्थिरता प्रदर्शन और विभिन्न ईएसजी आयामों [8] पर प्रभाव पर रिपोर्ट करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। पारदर्शी रिपोर्टिंग के माध्यम से, कंपनियां निवेशकों सहित हितधारकों को अपने स्थिरता प्रयासों और प्रगति के बारे में बता सकती हैं। इसके अलावा, जलवायु संबंधी वित्तीय खुलासे पर कार्य बल (TCFD) जलवायु संबंधी जोखिमों और निवेश निर्णय लेने के अवसरों को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा के रूप में उभरा है [9]। यह कंपनियों को जलवायु से संबंधित वित्तीय जानकारी का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो के भीतर जलवायु संबंधी जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने में मदद मिलती है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश निर्णयों में ESG कारकों को एकीकृत करना आवश्यक है। सतत निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, और संसाधन-कुशल समाधान [10] जैसे टिकाऊ क्षेत्रों की ओर पूंजी को निर्देशित करके पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देता है। यह उचित श्रम प्रथाओं, सामुदायिक जुड़ाव और विविधता को प्राथमिकता देने वाली कंपनियों का समर्थन करके सामाजिक समावेशिता को भी प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त, स्थायी निवेश सुशासन प्रथाओं पर जोर देता है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण शामिल हैं। शामिल पर्यावरण और सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करके स्थायी निवेश प्रथाएं अधिक टिकाऊ वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं।

सतत निवेश के लिए भारत की अवधारणा

भारत ने दीर्घकालिक आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक विकास की अपनी खोज में स्थायी निवेश के महत्व को स्वीकार किया है। सतत निवेश की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और पर्यावरण और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के प्रयासों के अनुरूप है [11]। भारत सरकार ने स्थायी निवेश प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों और पहलों को लागू किया है। ऐसी ही एक पहल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स, जो एसडीजी हासिल करने की दिशा में भारतीय राज्यों की प्रगति का आकलन करता है और राज्यों को स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है [12]। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट सिटीज मिशन बुनियादी ढांचे, परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन [13] में निवेश के माध्यम से स्थायी और समावेशी शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा, भारत ने स्थायी निवेश पहलों का समर्थन करने के लिए समर्पित वित्तीय संस्थानों की स्थापना की है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) कृषि, ग्रामीण विकास और सतत आजीविका से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है [14]। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देती है, भारत के अपने ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लक्ष्य में योगदान करती है [15]। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) भारत के स्थायी निवेश परिदृश्य में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाती है। सरकार ने अक्षय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ कृषि जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ सहयोग किया है। ये साझेदारियाँ सतत विकास पहलों को चलाने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सतत निवेश की भूमिका

सतत निवेश सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया भर के व्यवसायों और निवेशकों के लिए निवेश निर्णयों में स्थिरता का एकीकरण तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है [16]। यहां, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थायी निवेश की प्रमुख भूमिकाओं का पता लगाते हैं।

सतत आपूर्ति श्रृंखला: सतत निवेश स्थायी आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास को प्रोत्साहित करता है, जिसमें उत्पादन और वितरण प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार प्रथाओं को शामिल किया गया है [17]। स्थायी आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश करके, व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए उपभोक्ता मांग को पूरा कर सकते हैं और अपने संचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं [18]।

बाजार पहुंच और निवेशक आकर्षण: सतत निवेश प्रथाएं नए बाजारों के द्वार खोल सकती हैं और व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच बढ़ा सकती हैं। कई देशों ने स्थिरता मानकों और विनियमों को लागू किया है, जिससे बाजार में प्रवेश और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी के लिए स्थायी निवेश को एक शर्त बना दिया गया है। इसके अलावा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह तेजी से उन देशों की ओर निर्देशित होता है जो स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि निवेशक नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अन्य स्थायी क्षेत्रों में अवसर तलाशते हैं।

सहयोग और ज्ञान हस्तांतरण: सतत निवेश देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा दे सकता है, जिससे स्थिरता में प्रौद्योगिकी, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का हस्तांतरण हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से, देश एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं और संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी [16] जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह ज्ञान हस्तांतरण विकासशील देशों की सतत प्रथाओं को अपनाने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता को बढ़ा सकता है।

व्यापार समझौतों और नीतियों पर प्रभाव: सतत निवेश ने व्यापार समझौतों और नीतियों के निर्माण को प्रभावित किया है। कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में अब सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और श्रम अधिकारों [19] पर प्रावधान शामिल हैं। सतत निवेश प्रथाएं इन प्रावधानों के साथ संरेखित हो सकती हैं, व्यापार समझौतों के अनुपालन की सुविधा और भाग लेने वाले देशों के लिए बाजार पहुंच में सुधार कर सकती हैं।

वित्तीय प्रदर्शन और जोखिम प्रबंधन: सतत निवेश ने पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का प्रबंधन करते हुए वित्तीय रिटर्न देने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। वित्तीय रूप से व्यवहार्य और लचीली कंपनियों [20] की पहचान करने के लिए निवेशक अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में ESG कारकों पर तेजी से विचार कर रहे हैं। निवेश रणनीतियों में स्थिरता को एकीकृत करके, निवेशक जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और नियामक परिवर्तनों से जुड़े जोखिमों को कम कर सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिरता और दीर्घकालिक विकास में योगदान मिलता है।

सतत निवेश के लिए भारत की अवधारणा का प्रभाव

स्थायी निवेश के लिए भारत की अवधारणा का अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, समाज और शासन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। सतत विकास के लिए देश की प्रतिबद्धता और निवेश प्रथाओं में स्थिरता सिद्धांतों के एकीकरण से

सकारात्मक परिवर्तन और परिवर्तनकारी परिणाम सामने आए हैं। यहां, हम स्थायी निवेश के लिए भारत की अवधारणा के प्रमुख प्रभावों की जांच करते हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव: भारत की स्थायी निवेश पहलों ने पर्यावरण संरक्षण और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में संक्रमण में योगदान दिया है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा, ने देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार किया है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया है [21]। इसके अलावा, स्थायी निवेश ने जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, और टिकाऊ कृषि, संसाधन दक्षता और पर्यावरणीय नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए पहल का समर्थन किया है।

सामाजिक प्रभाव: भारत में सतत निवेश ने सामाजिक विकास और समावेशिता को बढ़ावा दिया है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और किफायती आवास जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से, अवधारणा ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया है [22]। इसके अतिरिक्त, स्थायी निवेश जिम्मेदार व्यवसाय प्रथाओं को बढ़ावा देता है, जिसमें उचित श्रम मानक, मानवाधिकार संरक्षण और सामुदायिक जुड़ाव शामिल हैं, जिससे सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण सुनिश्चित होता है [23]।

आर्थिक प्रभाव: स्थायी निवेश के लिए भारत की अवधारणा का आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्थायी क्षेत्रों में निवेश, जैसे अक्षय ऊर्जा, ने घरेलू और विदेशी दोनों निवेशों को आकर्षित करते हुए, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है। स्थायी उद्योगों के विकास ने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, खासकर ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में [24]। इसके अलावा, स्थायी निवेश ने नवाचार और हरित व्यवसायों के उद्भव को प्रोत्साहित किया है, उद्यमशीलता और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा दिया है।

शासन और नीति प्रभाव: स्थायी निवेश के लिए भारत की अवधारणा ने शासन और नीतिगत ढांचे को प्रभावित किया है। सरकार ने व्यवसायों द्वारा स्थायी प्रथाओं, रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए नियम और दिशानिर्देश पेश किए हैं। कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं में स्थिरता के विचारों के एकीकरण ने पारदर्शिता, जवाबदेही और जोखिम प्रबंधन [25] में सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, अवधारणा ने सतत विकास एजेंडा और ढांचे को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नीतिगत चर्चाओं और सहयोगों को आकार दिया है।

चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाएँ

जबकि भारत ने स्थायी निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, इसके प्रभाव को और बढ़ाने के लिए कई चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाओं को संबोधित करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों को समझने और भविष्य की दिशाओं पर विचार करने से भारत में स्थायी निवेश के लिए अधिक मजबूत और प्रभावी रूपरेखा तैयार करने में मदद मिल सकती है।

वित्त पोषण तक पहुंच: भारत में सतत निवेश के लिए वित्तपोषण तक पहुंच एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। समर्पित वित्तीय संस्थानों और सरकारी पहलों की उपलब्धता के बावजूद, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) और स्टार्टअप्स [26] के लिए स्थायी परियोजनाओं के लिए किफायती और दीर्घकालिक वित्तपोषण विकल्पों तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता है। वित्तीय संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और निजी निवेशकों के बीच सहयोग अभिनव वित्तपोषण तंत्र विकसित करने और स्थायी निवेश की बाधाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है।

क्षमता निर्माण और जागरूकता: स्थायी निवेश प्रथाओं के बारे में क्षमता निर्माण और जागरूकता बढ़ाना उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। निवेशकों, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों सहित हितधारकों को निवेश निर्णय लेने में स्थिरता को एकीकृत करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और उपकरणों से लैस होने की आवश्यकता है [27]। प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान क्षमता बढ़ाने और स्थायी निवेश प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

डेटा उपलब्धता और पारदर्शिता: पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) कारकों पर विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता और पारदर्शिता स्थायी निवेश के लिए एक चुनौती है। कंपनियों और परियोजनाओं की स्थिरता के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए

निवेशकों को सटीक और मानकीकृत जानकारी की आवश्यकता होती है। डेटा संग्रह, रिपोर्टिंग ढांचे और प्रकटीकरण प्रथाओं में सुधार के प्रयास सूचित निवेश निर्णयों की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और स्थायी निवेश में विश्वसनीयता और विश्वास को मजबूत कर सकते हैं।

नीति और नियामक ढांचा: सतत निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीति और नियामक ढांचे का निरंतर विकास और वृद्धि आवश्यक है। स्पष्ट और सुसंगत नीतियां, नियम और प्रोत्साहन एक सक्षम वातावरण बना सकते हैं और निवेशकों के लिए निश्चितता प्रदान कर सकते हैं [28]। सरकार को विशिष्ट क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने, नवाचार को बढ़ावा देने और स्थायी निवेश को आकर्षित करने वाले व्यापक और सहायक ढांचे को विकसित करने के लिए प्रासंगिक हितधारकों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

सहयोग और भागीदारी: स्थायी निवेश की सफलता के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी महत्वपूर्ण है। सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठनों और शिक्षाविदों से जुड़े बहु-हितधारक जुड़ाव ज्ञान साझा करने, संसाधन जुटाने और स्थायी निवेश पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं [29]। सार्वजनिक-निजी भागीदारी, उद्योग सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, निवेश बढ़ा सकते हैं और जटिल स्थिरता चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। आगे देखते हुए, भारत में स्थायी निवेश के लिए भविष्य की दिशाओं में प्रयासों को बढ़ाना, तकनीकी प्रगति का लाभ उठाना और उभरते क्षेत्रों में स्थिरता को एकीकृत करना शामिल है। ब्लॉकचैन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी डिजिटल तकनीकों को अपनाने से टिकाऊ निवेश [27] में पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता और प्रभाव मापन में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, परिवहन अर्थव्यवस्था, स्वच्छ परिवहन और टिकाऊ पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों की खोज से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरणीय स्थिरता को गति मिल सकती है।

निष्कर्ष:

सतत निवेश के लिए भारत की अवधारणा सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समावेशी आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में उभरी है। इसने पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था और शासन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला है। भारत में सतत निवेश से स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार हुआ है, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई है, और संसाधन दक्षता और पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा मिला है। इसने सीमांत समुदायों के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में भी सुधार किया है और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं के माध्यम से सामाजिक कल्याण सुनिश्चित किया है। आर्थिक रूप से, स्थायी निवेश ने आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित किया है, निवेश आकर्षित किया है, और रोजगार सृजित किया है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उद्यमिता और विविधीकरण को बढ़ावा दिया है। सस्टेनेबिलिटी के लिए भारत की प्रतिबद्धता ने इसके लचीलेपन को बढ़ाया है और इसे सतत विकास में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। शासन और नीतिगत ढांचे में स्थिरता के एकीकरण से पारदर्शिता, जवाबदेही और जोखिम प्रबंधन में सुधार हुआ है। भारत के प्रयासों ने अन्य देशों को स्थायी निवेश को प्राथमिकता देने और समान दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा मिला है। चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे वित्तपोषण पहुंच में सुधार, क्षमता निर्माण, डेटा पारदर्शिता सुनिश्चित करना और नीतिगत ढांचे को बढ़ाना। इन चुनौतियों से पार पाने और स्थायी निवेश को आगे बढ़ाने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।

संदर्भ सूची:

- [1]. World Bank. (2020). India. Retrieved from <https://data.worldbank.org/country/india>
- [2]. Draz, M. U., & Ahmad, F.. (2018, January 1). Financial Crises and Key Economic Sectors of China and India: A Comparative Review of 1991-2010. SHS Web of Conferences, 56, 04002. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185604002>

- [3]. Carmona, S., Farazmand, H., & Sosvilla-Rivero, S. (2020). Sustainable investment: A bibliometric analysis. *Journal of Cleaner Production*, 244, 118853.
- [4]. Rennings, K., Wiggering, H., & Hoffmann, E. (2018). Sustainable investment: Concepts, methodologies, and challenges. *Journal of Cleaner Production*, 181, 1-5.
- [5]. UNCTAD. (2020). *World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic*. United Nations Conference on Trade and Development.
- [6]. García-Gómez, F. J., Prieto, V. F. R., Sánchez-Lite, A., Fuentes-Bargues, J. L., & González, C. C.. (2021, June 8). An Approach to Sustainability Risk Assessment in Industrial Assets. *Sustainability*, 13(12), 6538. <https://doi.org/10.3390/su13126538>
- [7]. Principles for Responsible Investment (PRI). (n.d.). About PRI. Retrieved from <https://www.unpri.org/pri/about-the-pri>
- [8]. Global Reporting Initiative (GRI). (n.d.). About GRI. Retrieved from <https://www.globalreporting.org/about-gri/>
- [9]. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). (n.d.). About the TCFD. Retrieved from <https://www.fsb-tcfid.org/about/>
- [10]. Lacalle, D.. (2020, February 14). The Importance of Profit and Sound Financing in Socially Responsible Investment. *Journal of Business Accounting and Finance Perspectives*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.35995/jbafp2020011>
- [11]. Government of India. (2019). National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business. Retrieved from https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesActNotification_07nov2019.pdf
- [12]. Ministry of Housing and Urban Affairs. (2020). Smart Cities Mission. Retrieved from <https://smartcities.gov.in/>
- [13]. NITI Aayog. (2020). SDG India Index & Dashboard 2019-20. Retrieved from <https://niti.gov.in/sdg-india-index-dashboard-2019-20>
- [14]. Soni, K. K.. (2018, November 21). Is Malnutrition Still a Serious Problem in India? A Comprehensive Review. *Journal of Medical Science and Clinical Research*, 6(11). <https://doi.org/10.18535/jmscr/v6i11.96>
- [15]. Kocmanová, A., Dočekalová, M., Meluzín, T., & Škapa, S.. (2020, October 10). Sustainable Investing Model for Decision Makers (Based On Research of Manufacturing Industry in the Czech Republic). *Sustainability*, 12(20), 8342. <https://doi.org/10.3390/su12208342>
- [16]. UNCTAD. (2020). *World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic*. United Nations Conference on Trade and Development.
- [17]. Kato, T., & Hiroi, Y.. (2021, November 4). Wealth disparities and economic flow: Assessment using an asset exchange model with the surplus stock of the wealthy. *Plos One*, 16(11), e0259323. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259323>
- [18]. Taliento, M., Favino, C., & Netti, A.. (2019, March 22). Impact of Environmental, Social, and Governance Information on Economic Performance: Evidence of a Corporate ‘Sustainability Advantage’ from Europe. *Sustainability*, 11(6), 1738. <https://doi.org/10.3390/su11061738>
- [19]. Ito, H.. (2022, August 31). On the Correlation between Market Risk Premiums and SDGs. *Communications of the Japan Association of Real Options and Strategy*, 12(1), 35-50. https://doi.org/10.12949/cjaros.12.1_35

- [20]. Przychodzen, J., Pascual, F. G., Przychodzen, W., & Larreina, M.. (2016, October 24). ESG Issues among Fund Managers—Factors and Motives. *Sustainability*, 8(10), 1078. <https://doi.org/10.3390/su8101078>
- [21]. Sgammini, R.. (2023, January 14). A Comparative Risk-adjusted Performance Evaluation of South African SRI Funds and the FTSE/JSE over the Covid-19 Period. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 13(1), 46-55. <https://doi.org/10.32479/ijefi.13717>
- [22]. Government of India. (2019). National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business. Retrieved from https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesActNotification_07nov2019.pdf
- [23]. NITI Aayog. (2020). SDG India Index & Dashboard 2019-20. Retrieved from <https://niti.gov.in/sdg-india-index-dashboard-2019-20>
- [24]. Kocmanová, A., Dočekalová, M., Meluzín, T., & Škapa, S.. (2020, October 10). Sustainable Investing Model for Decision Makers (Based On Research of Manufacturing Industry in the Czech Republic). *Sustainability*, 12(20), 8342. <https://doi.org/10.3390/su12208342>
- [25]. Zhao, H., Zhang, J., & Ge, Y.. (2021, July 9). Operation mode selection of NIMBY facility Public Private Partnership projects. *Plos One*, 16(7), e0254046. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254046>
- [26]. An, H., Yan, W., Bian, S., & Ma, S.. (2019, October 1). Rain Monitoring with Polarimetric GNSS Signals: Ground-Based Experimental Research. *Remote Sensing*, 11(19), 2293. <https://doi.org/10.3390/rs11192293>
- [27]. UNEP FI. (2019). Principles for Responsible Banking. Retrieved from <https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/>
- [28]. Zhang, Zhendong et al. (2021, January 1). Solar Radiation Intensity Probabilistic Forecasting Based on K-Means Time Series Clustering and Gaussian Process Regression. *Ieee Access*, 9, 89079-89092. <https://doi.org/10.1109/access.2021.3077475>
- [29]. Fan, L., Wang, Y., Fang, X., & Jiang, J.. (2022, October 1). To Predict the Power Generation based on Machine Learning Method. *Journal of Physics Conference Series*, 2310(1), 012084. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2310/1/012084>
- [30]. World Economic Forum. (2020). The Future of Sustainable Investment. Retrieved from <https://www.weforum.org/whitepapers>

Cite this Article

POOJA BHAGAT, “सतत निवेश के लिए भारत की अवधारणा: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भूमिका और प्रभाव”, *International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology (IJMRAST)*, ISSN: 2584-0231, Volume 1, Issue 4, pp. 38-44, November 2023. **Journal URL:** <https://ijmrast.com/>

